Request for immediate sanction of international leather complex in Andhra Pradesh

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, India has exported more than Rs.9000 crores worth of leather and leather-related manufactured goods in 2001-02 to other countries of the world. This clearly shows that there is an immense potential of not only earning foreign exchange but also employment opportunities through the leather exports. Taking cue from this and looking at the advantages that the State of Andhra Pradesh has, the Government of Andhra Pradesh has prepared a master plan to develop a number of leather industrial parks to attract Foreign Direct Investment from tanneries abroad. To achieve this objective, the Government of Andhra Pradesh requested the Government of India for setting up of an international leather complex at Krishnapatnam in Muttkur Mandal of Nellore District of Andhra Pradesh. The Government of Andhra Pradesh has also earmarked 1,000 acres of land for this purpose. On the request made by the Government of Andhra Pradesh, the Government of India approved the proposal in principle. The chief Minister of Andhra Pradesh had also written a letter to this effect on 17th April, 2003, as to give a fillip to the leather industry in Andhra Pradesh. The hon. Minister of Information, Government of Andhra Pradesh, had also urged the Minister of Commerce and Industry in the third week of May 2003, and requested him to immediately accord formal sanction for the international leather complex.

Hence, I request, through you, Sir, the hon. Minister of Commerce and Industry to immediately sanction the proposal for setting up of a international leather complex in Andhra Pradesh. Thank you.

Problems of weavers in Uttar Pradesh

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बुनकरो की समस्याओ की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, मुबारकपुर, जलालपुर मे बुनकरों की बहुत बडी आबादी है। ये बुनकर कई प्रकार का कपड़ा और गलीचे बनाते हैं जो कि विदेश में जाता है। इसके बावजूद आज यहां के बुनकर बहुत ही दयनीय हालत में हैं। इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रथम तो इनके बनाए हुए सामान का अब कोई खरीददार नहीं है। पहले सरकार इनके द्वारा निर्मित कपडे और अन्य चीजें लिया करती थी पर अब यह बंद हो गया है। इनको मार्केट में अपना सामान बेचने मे बहुत मुश्किले आती हैं। इसके लिए एक विशेष मार्केट की व्यवस्था की जरूरत है। इनकी एक

बहुत बड़ी समस्या बिजली की कमी है। इन्हे बहुत ही कम बिजली मिलती है और अगर मिलती भी है तो अनियमित रूप मे जिससे और कई गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। इन सब कारणों से ये बुनकर अपना धरना, प्रदर्शन करते रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप स्पीच नही दे सकते हैं। आप रिटन टैक्स्ट पढ़िये।

श्री दारा सिंह चौहान : उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी एक सांसदों की समिति बनाकर जॉच की जाए या न्यायिक जॉच कराई जाए, वरना इसके परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय मे हस्तक्षेप करे तथा बुनकरो के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की घोषणा करे।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे अपने आपको संबद्ध करता हूं।

श्री मुनव्वर हसन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Repatriation of Indian prisoners lodged in Pakistani jails

श्री.बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद महोदय, भारत सरकार और संसार के देश इस बात से अवगत हैं कि सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान किसी न किसी स्तर पर बंदी बनाए गए 54 भारतीय योद्धा आज भी पाकिस्तान की जेलो में बंद हैं और वहां की जेल यातनाएं भुगत रहे हैं। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान से समय समय पर कूटनीतिक चर्चा एवं शांतिवार्ता करने वाली केन्द्र सरकार ने इन 54 बंदियों के लिए क्या कभी कोई मुद्दा इनकी वापसी या रिहाई को बनाया? पिछले तीस बत्तीस वर्षो में केन्द्र एक दिन भी बिना सरकार के नहीं रहा। क्या आज की कूटनीतिक वार्ता में हमारी सरकार इन बंदियो की रिहाई को अपने ऐजेंडे में रखती है? इन रणजुझारे सेनानियो के परिजन यहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे वहां भारत सरकार की कूटनीतिक पहल और उसकी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडलो और शिष्टमंडलो ने इस दिशा मे कोई प्रयत्न किया? आज उनके कुशलक्षेम के क्या समाचार हैं? यह एक गंभीर और सेना तथा समरभूमि की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत सरकार को देश को सारी स्थिति से अवगत रखना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम कार्यवाही करनी चाहिए। अपनी जवानी का सोना समरभूमि मे स्वाहा करने वाले योद्धाओ को ससम्मान अपनी मातृभूमि में वापिस लाने की मांग भारत माता की मांग है। धन्यवाद।

Request for allocation of funds under Prime Minister's Gram Sadak Yojna Phase-IV to Andhra Pradesh

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, my Special Mention is pertaining to Allocation of funds under Prime Minister Gram Sadak Yojna Phase-IV.